भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1223
जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है ।
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

डिजी-ग्राम परियोजना

1223. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव राईक निम्बालकर :
श्री अरुण साव :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजी-ग्राम परियोजना का वर्तमान/संशोधित ब्यौरा क्या है और आज की तिथि में उक्त परियोजना के अंतर्गत कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है;
(ख) क्या सरकार को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से और अधिक डिजी-ग्राम स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में उक्त परियोजना के विस्तार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का उक्त परियोजना के अंतर्गत सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीएस) का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) उक्त परियोजना पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का उक्त परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों विशेषकर महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसरों को सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): देशभरके 700 गांवों में प्रायोगिक आधार पर सरकार से नागरिक, व्यवसाय से नागरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनि की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना शुरू की गई थी ।

(ख) : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) : सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का विस्तार परियोजना के तहत परिकल्पित गतिविधि का हिस्सा नहीं है।

(ङ) : इस परियोजना के तहत 60.00 करोड़ रुपये की राशि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई है और इसमें से 54.97 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग किये जाने की सूचना दी गई है ।

(च) : परियोजना में डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और कौशल विकास शामिल है, लाभार्थियों में महिलाएं भी शामिल हैं।

****